सत्यमेव जयते

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय
की उपलब्धियां

फरवरी 2024

कोयला
समुदाय
देखभाल

जब हम Coal Production बढ़ाते हैं तो Power Generation बढ़ने के साथ ही steel, Aluminum, फर्टिलाइजर, सीमेंट जैसे तमाम दुसरे सेक्टर्स में Production और Processing पर भी Positive Impact होता है

उपलब्धियों पर एक नजर

- कोयला मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाकर; प्रमाणित कोयला संसाधनों को बढ़ाने पर जोर देते हुए अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाकर और कोयले के शीघ्र निष्कर्षण के लिए आवश्यक अवसंरचना विकसित करते हुए कोयले के उत्पादन में वृद्धि करना है ताकि पर्यावरण अनुकूल और संधारणीय तरीके से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा किया जा सके।

सुधार

वाणिज्यिक कोयला खनन:

माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाणिज्यिक कोयला खनन का शुभारंभ करते हुए **18 जून, 2020** को महत्वपूर्ण सुधार की शुरुआत की। इस सुधार में नई पारदर्शी नीलामी प्रणाली के कार्यान्वयन को शामिल किया गया था ताकि कोयला उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी जा सके, आयात कम किया जा सके और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

वाणिज्यिक कोयला खनन घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

- **खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957:** खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत, 35 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

- **कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (सीएमएसपी अधिनियम) के तहत खानों का आवंटन:** 1993 से आवंटित 218 कोयला ब्लॉकों में से 204 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद, देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने सीएमएसपी अधिनियम, 2015 को अधिनियमित किया। पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी, उत्पादन में वृद्धि, सरकारी राजस्व, रोजगार, पर्यावरणीय संधारणीयता और उदार पात्रता शर्तें, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए इस अधिनियम के तहत 122 कोयला खानों का सफलतापूर्वक आवंटन किया गया था।

- **कोयला कंपनियों के गैसीकरण संयंत्रों के लिए कोयला लिंकेज -** कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) को अपने स्वयं के गैसीकरण संयंत्रों को कोयले का दीर्घकालिक आबंटन प्रदान करने की अनुमति दी गई है। इससे देश में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।

- **कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि का उपयोग:**
  मंत्रालय ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देश में उन भूमियों पर विचार किया जाता है जो कोयला खनन गतिविधियों के लिए अब उपयुक्त या आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं, या ऐसी भूमि जिसमें खनन किया जा चुका है या जिसका कन्वेयर सिस्टम, कोल हैंडलिंग प्लांट, रेलवे साइडिंग आदि जैसी विभिन्न कोयला अवसंरचना विकास गतिविधियों

- **खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2022 -**
  मंत्रालय ने खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर) संशोधन किया है ताकि इसके उपबंधों को कानूनी रूप दिया जा सके। यह संशोधन एमसीआर के अड़सठ (68) उपबंधों को कानूनी रूप देकर सरकार की "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" नीति को बढ़ावा देता है, जबकि दस (10) उपबंधों के लिए शास्ति कम करता है।

विपणन सुधार

- कोयले की ई-नीलामी के लिए सिंगल विंडो: कोल इंडिया लिमिटेड की क्षेत्रीय ई-नीलामी विंडो को समाप्त करते हुए वर्ष 2022 में, सरकार ने कोयला कंपनियों के लिए एक नए ई-नीलामी कार्यतंत्र को मंजूरी दी है। यह सिंगल ई-नीलामी विंडो व्यापारियों सहित सभी क्षेत्रों की मांग को पूरा करेगी, बाजार की विकृतियों को दूर करेगी, प्रचालन क्षमता में वृद्धि होगी अंततः घरेलू कोयले की मांग में वृद्धि होगी।

- एनसीडीपी में संशोधन: कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए नई कोयला वितरण नीति, 2007 में संशोधन किया गया है ताकि सीआईएल/एससीसीएल की बंद/परित्यक्त/समाप्त खानों से पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कोयले बिक्री की अनुमति दी जा सके।

इन सुधारों से राष्ट्र की प्रगति की गति को तेजी मिलेगी, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, किफायत मूल्यों पर एक स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होगी, लोग लाभान्वित होंगे और नए व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा।

नीतिगत पहलें

- **थर्ड-पार्टी सैपलिंग द्वारा कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करना :** ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए, कोयले के गुणवत्ता प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया है। सीआईएल/एससीसीएल के सभी उपभोक्ताओं के पास स्वतंत्र थर्ड-पार्टी सैपलिंग एजेंसियों (टीपीएसए) के माध्यम से आपूर्ति के गुणवत्ता मूल्यांकन का विकल्प है। विद्युत/गैर-विद्युत क्षेत्रों के सभी उपभोक्ता किसी भी पैनलबद्ध एजेंसी की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

- **मिशन कोकिंग कोयला:** कोयला मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को बढ़ावा देने के लिए मिशन कोकिंग कोल शुरूआत की। घरेलू कच्चे कोयले का उत्पादन वर्ष 2030 तक 140 मि.ट. तक पहुंचने की संभावना है। सीआईएल ने मौजूदा खानों से उत्पादन को बढ़ाने तथा नई खानों की पहचान की योजना बनाई है। मंत्रालय ने निजी क्षेत्रों को 16 कोकिंग कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया है और इनसे 2025 तक उत्पादन शुरु होने की संभावना है।

- **राजस्व शेयरिंग मॉडल पर बंद पड़ी खानों को पुन: खोलना :** राजस्व शेयरिंग आधार पर पुन: खोलने के लिए 34 परित्यक्त खानों को अभिनिर्धारित किया गया है। जिनमें से 19 खानों के लिए एलओए जारी कर दिया गया है। बंद पड़ी खानों से राष्ट्र को नुकसान होता है क्योंकि बड़ी मात्रा में भंडारों का निष्कर्षण नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मंत्रालय राजस्व-शेयरिंग मॉडल में खानों की पेशकश करता है जिसमें इन परित्यक्त खानों को प्रचालन में वापस लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल

विद्युत क्षेत्र को कोयला लिंकेज का अनुदान:-

स्कीम फॉर हारनेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया (शक्ति), 2017, का उद्देश्य कोयला लिंकेज को नामांकन आधार से नीलामी/टैरिफ-आधारित बोली में परिवर्तित करना है। वर्ष 2019 में संशोधित किए गए थे जिसमें विद्युत संयंत्रों को लघु, मध्यम तथा दीर्घकालिक कोयला लिंकेज प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों का प्रावधान था। शक्ति नीति के तहत कोयला आपूर्ति मध्यम एवं अल्पावधिक विद्युत क्रय समझौते के लिए अब उपलब्ध है।

कोयला खान सर्वेक्षण एवं प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) तथा 'खनन प्रहरी' सीएमएसएमएस, एक वेब आधारित एप्लिकेशन है तथा 'खनन प्रहरी' एक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन है जिसे कोलफील्ड क्षेत्रों में लीजहोल्ड सीमा के भीतर हो रही किसी भी प्रकार की अवैध कोयला खनन कार्यकलापों का पता लगाने, निगरानी करने तथा कार्रवाई करने के लिए दिनांक 04.07.2018 को प्रारंभ किया गया था।

कोयला धारक राज्यों के साथ राजस्व शेयरिंग

कोयला धारक राज्यों को भुगतान किए गए राजस्व से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक विकास और नागरिकों के लिए 'ईज ऑफ लीविंग' में सुधार हुआ है।

कोयला पीएसयू ने 2014-15 से कोयला धारक राज्यों को कुल **1,52,696** करोड़ रुपये का राजस्व वितरित किया।

कोयला धारक राज्यों के साथ शेयर किया गया राजस्व

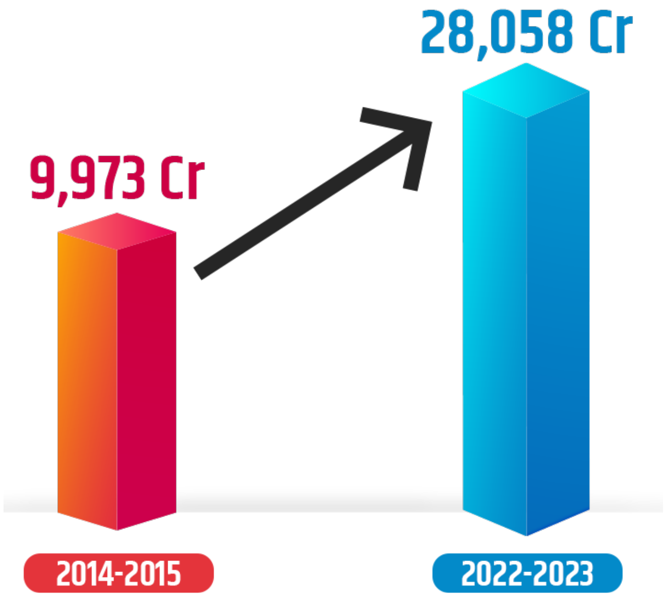

कोयला उत्पादन तथा प्रेषण

- सकल वार्षिक कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में 609.18 मि.ट. से वित्त वर्ष 2022-23 में 893.19 मि.ट. तक बढ़ गया है जिससे पिछले 9 वर्षों में **47% की भारी वृद्धि** देखी गई है।

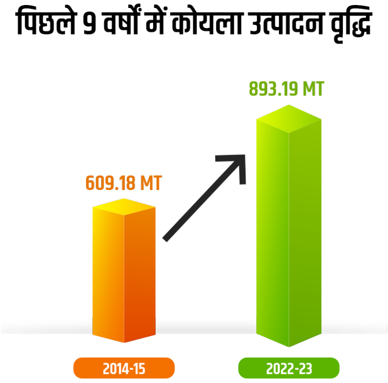

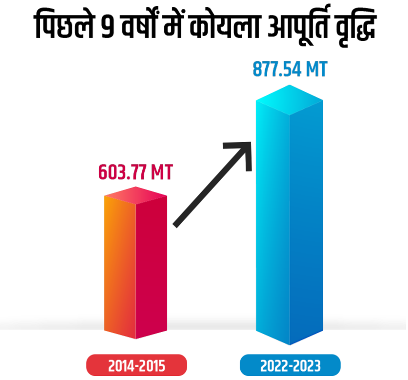

- पिछले वित्त वर्ष के उत्पादन अर्थात 785.39 मि.ट. की तुलना में इसी अवधि में 12.14% की वृद्धि के साथ वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 (फ़रवरी 2024 तक) तक के दौरान देश में कोयला उत्पादन 880.72 मि.ट. था।

- पिछले वित्त वर्ष की आपूर्ति अर्थात 794.41 मि.ट. की तुलना में इसी अवधि में 11.08% की वृद्धि के साथ वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 (फ़रवरी 2024 तक) के दौरान देश में कोयला आपूर्ति 882.44 मि.ट. था।

आयात में कमी

- वर्ष 2014-15 से आयात निर्भरता निरंतर कम हो रही है। आयात निर्भरता जो 2014-15 के दौरान 26% थी, वर्ष 2022-23 के दौरान घटकर 21% हो गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान नवंबर 2023 तक, आपात निर्भरता 17.94% है जो पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के इसी अवधि के दौरान 18.91% थी।
- वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, अप्रैल से नवंबर तक घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयला आयात पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, घटकर 44.30% तक हो गई है।
- हालाँकि, मौजूदा वित्तीय वर्ष के नवंबर 2023 तक कोयले के आयात की कुल मात्रा में स्थिरता बनी रही, लेकिन कोयले के आयात शुल्क में 32.04% की उल्लेखनीय कमी आई है। इस कटौती के परिणामस्वरूप 11.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पर्याप्त बचत हुई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में रुपये के संदर्भ में 82546.32 करोड़ रुपये (28.95%) है।

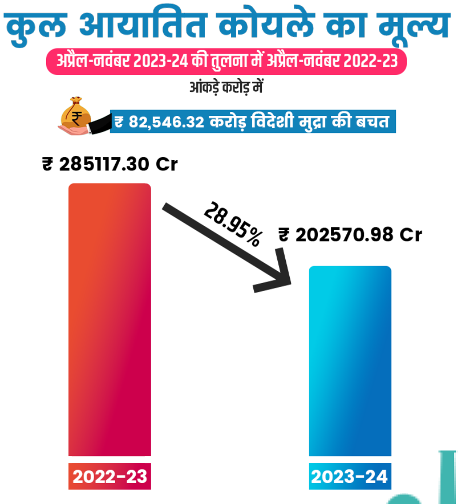

वाणिज्यिक खनन

मंत्रालय ने **155 कोयला खानों** का सफलतापूर्वक आवंटन किया है जिसमें से **57 खानें** प्रचालनरत हैं तथा शेष विकास के विभिन्न चरण में है। इन खानों की संचयी पीआरसी (अधिकतम दर क्षमता) **548.37 मि.ट.** थी। इसके अलावा, कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला खानों से कोयला उत्पादन वर्ष 2014-15 में **52.70 मि.ट.** से बढ़कर **132.83%** की वृद्धि के साथ वर्ष 2022-23 में **122.7 मि.ट.** हो गया है।

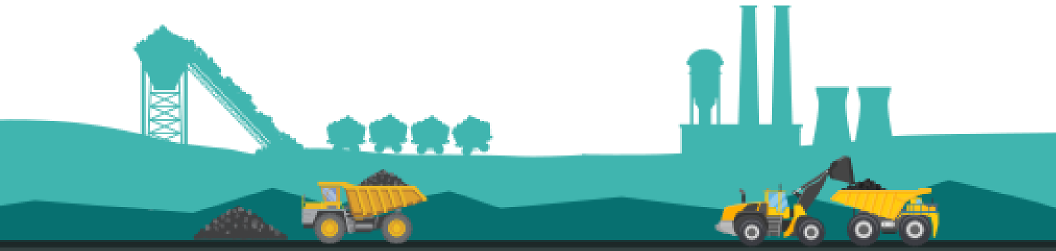

पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसका समग्र आर्थिक वृद्धि उपभोग, मांग पर गुणात्मक तथा ट्रिकल डाउन प्रभाव है और औद्योगिक वृद्धि करता है, रोजगार का सृजन तथा स्थायी अवसंरचना का निर्माण करता है जिससे एक लंबी अवधि में देश को स्थायी लाभ प्राप्त होते हैं।

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पीएसयू, भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में सहायता एवं योगदान करने के लिए पूंजीगत व्यय करने में अग्रणी है। पिछले 10 वर्षों में (वित्त वर्ष 14-15 से वित्त वर्ष 22-23) की अवधि में कोयला पीएसयू द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय (15780 करोड़ रू. का औसत) निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पीएसयू	करोड़ रू. में
1	कोल इंडिया लिमिटेड	89,216
2	एनएलसीआईएल	35,725
3	एससीसीएल	17,074
	कुल	**1,42,015**

मोटर चालित ट्राइसाइकिलों का वितरण

परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना

कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू किए गए परिसंपत्ति मुद्रीकरण के अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम में कम उपयोग की गई परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में बेहतर प्रदर्शन किया है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत संपूर्ण उपलब्धि निम्नानुसार है:

रू.करोड़ में

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2021-22	3,394	40,105
2022-23	30,000	57,180
कुल	**33,394**	**97,285**

बाजार पूंजीकरण

रू.करोड़ में

क्र.सं.	कंपनी का नाम	01.04.2021 की स्थिति के अनुसार बाजार पूंजी	06.02.2024 की स्थिति के अनुसार बाजार पूंजी	16.01.2024 की स्थिति के अनुसार बाजार पूंजी	पिछले वर्षों में बाजार पूंजी में % वृद्धि/कमी
1	सीआईएल	81,483	2,69,835	438	231.15%
2	एनएलसीआईएल	7,065	38,832	142	449.66%

जीईएम के माध्यम से खरीद

- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, जीईएम के माध्यम से वस्तुएं और सेवाओं की खरीद हेतु कोयला मंत्रालय के लिए जीईएम द्वारा तय किए गए लक्ष्य (इसके सीपीएसई सहित) 4000 करोड़ रू. था। लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि **4,278 करोड़ रू.** थी, जो कि 107% है।

- दिनांक 26.06.2023 को आयोजित समारोह में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा कोयला मंत्रालय, सीआईएल तथा एनएलसीआईएल को निम्नानुसार पुरस्कृत किया गया है:

''बेस्ट इंगेजमेंट''- कोयला मंत्रालय

''राइजिंग स्टार''-कोल इंडिया लिमिटेड

''समय पर भुगतान (सीपीएसई)''- एनएलसी इंडिया लिमिटेड

- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, जीईएम के माध्यम से वास्तविक खरीद **88,518 करोड़ रू.** (02 मार्च, 2024 तक) है जो कि **21,325 करोड़ रू.** के लक्ष्य का 415% है।

- सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में जीईएम के माध्यम से सकल खरीद में कोयला मंत्रालय प्रथम स्थान पर था। सभी सीपीएसई में जीईएम खरीद में **कोल इंडिया लिमिटेड (सहायक कंपनियों सहित) शीर्ष स्थान** (02 मार्च, 2024 तक) **पर** है।

रोजगार सृजन

- वित्तीय वर्ष 2014-15 से, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक रहे हैं, जिससे देश भर में लाखों नागरिकों की आजीविका में सहायता मिली है।

- युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने और नागरिक कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री जी की मौजूदा प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कोयला मंत्रालय ने मिशन मोड में 1 जुलाई, 2022 से रोज़गार मेले के आयोजन की शुरुआत के बाद से 9384 आवेदकों को रोजगार प्रदान किया है।

फर्स्ट माइल क्नेक्टिविटी परियोजनाएं

- खान से लोडिंग पोर्ट तक कोयले के पर्यावण अनुकूल एवं प्रभावी रूपांतरण को सुनिश्चित करने के लिए 885 मि.ट. क्षमता वाली 21,000 करोड़ रु. की 67 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत किया गया है, जिसमें से 11 परियोजनाएं शुरू हो गई हैं और शेष परियोजनाएं वित्त वर्ष 2028-29 तक पूरी हो जाएंगी। 16 और एफएमसी परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।
- कोयले के निर्बाध निष्कर्षण के लिए 103 एफएमसी (सीआईएल-95, एससीसीएल-5, नएलसीआईएल-3) को शुरू करने की योजना बनाई गई है। 291 मटीपीए क्षमता वाली 31 परियोजनाओं (29-सीआईएल एवं 2-एससीसीएल) को शुरू कर दिया गया है।
- कोयला निष्कर्षण में सुधार करने के लिए 14 रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है।

फर्स्ट माइल क्नेक्टिविटी पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कोयला परिवहन के इष्टतम उपयोग द्वारा समग्र लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाती है।

रेल परियोजनाएं

- पीएम गति शक्ति के अनुरूप, मंत्रालय ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के मिसिंग गैप को पूरा करने के लिए **26,000 करोड़ रु.** की **14 रेल परियोजनाएं** शुरू की हैं। इनमें से, आज तक 5 रेल परियोजनाओं को पहले ही शुरू कर दिया गया है।

ये रेलवे परियोजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और आजीविका में सहायता करते हुए क्षेत्र में कई नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी।

ऊर्जा दक्षता उपाय

मंत्रालय एलईडी लाइटों, ऊर्जा दक्ष एसी, पंखों, ई-वाहनों, वॉटर हीटरों, मोटरों, ऑटो टाइमरों और कैपसिटर बैंकों जैसी विभिन्न ऊर्जा-दक्ष पहलों को कार्यान्वित करते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के बाद से कोयला/लिग्नाइट पीएसयू में ऊर्जा दक्ष उपायों की निगरानी तत्परतापूर्वक करता रहा है। इन प्रयासों से 14.34 करोड़ कि.वा. यूनिट की बचत हुई, कुल मिलाकर 107.6 करोड़ रु. की बचत हुई, और 1.17 लाख टन तक सीओ2 उत्सर्जन कम हुआ, यह कोयला क्षेत्र में संधारणीयता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाता है।

नेवेली, एनएलसीआईएल

विविधीकरण

थर्ड-पार्टी सैंपलिंग द्वारा कोयला गुणवत्ता सुनिश्चित करना:

- सीआईएल और एनएलसीआईएल ने अपने कारोबार में विविधता लाने की योजना बनाई है।
- सीआईएल-मध्य प्रदेश में 1X660 मे.वा. टीपीपी और ओडिशा में 2X800 मे.वा. टीपीपी। सीसीईए ने दिनांक 18.01.2024 को (i) मध्य प्रदेश में 1X660 मे.वा. टीपीपी स्थापित करने के लिए एसईसीएल; (ii) ओडिशा में 2X800 मे.वा. टीपीपी स्थापित करने के लिए एमसीएल द्वारा इक्विटी निवेश हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
- एनएलसीआईएल – ओडिशा में 3X800 मे.वा. टीपीपी और उत्तर प्रदेश में 3X660 मे.वा. टीपीपी।

कोयला गैसीकरण:

- तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड निर्माणधीन है।
- मंत्रिमंडल ने कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए 8,500 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ एक स्कीम अनुमोदित की है।
- सीसीईए ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना के लिए सीआईएल एवं बीएचईएल के संयुक्त उद्यमों में सीआईएल द्वारा इक्विटी निवेश को अनुमोदित किया है।
- एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) ने लिग्नाइट से मेथनॉल प्लांट को स्थापित करने के लिए 02 यूनिटों हेतु निविदाएं आमंत्रित की है।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

- वित्त वर्ष 2022-2023 में, कोयला पीएसयू ने वर्ष 2014-15 में खर्च किए गए 360.5 करोड़ रु. की तुलना में 51.43% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए 546.04 करोड़ रु. आवंटित किए हैं।
- वित्त वर्ष 2023-2024 में, कोयला पीएसयू ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए 661.97 करोड़ रु. आवंटित किए हैं जिसमें से 464.01 करोड़ रु. का उपयोग फ़रवरी 2024 तक सीएसआर कार्यकलापों के लिए किया गया था।

सीएसआर व्यय संबंधी 9 वर्षों की उपलब्धियां

(आंकड़े करोड़ रु. में)

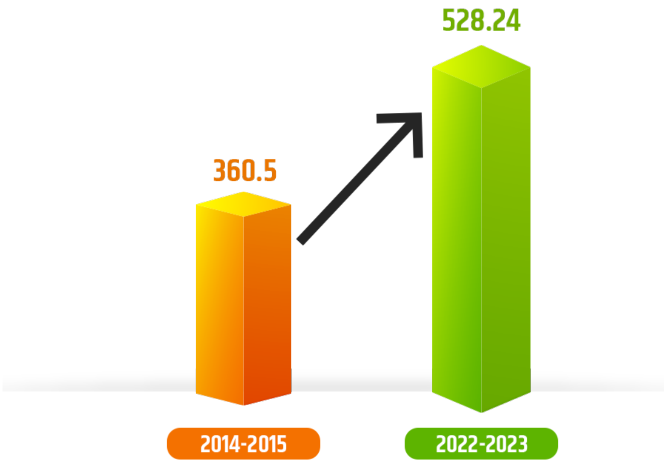

हमारे खनन कार्य स्थानीय समुदायों के समावेशी विकास और "सबका साथ, सबका विकास" के उद्देश्य के अनुरूप संरेखित हैं। कोयला पीएसयू की सीएसआर पहलें कमजोर लोगों के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करती है और समावेशन को बढ़ावा देती है। इससे निम्नानुसार कई लाभ मिलते हैं, जिसमें शामिल हैं:

- स्मार्ट क्लास के साथ स्कूल का बुनियादी ढांचा
- “सीसीएल के लाल/लाडली” स्कीम के तहत नि: शुल्क इंजीनियरिंग प्रवेश कोचिंग
- स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्तीय सहायता
- कौशल विकास कार्यक्रम
- खेल अवसंरचना का विकास।
- दिव्यांग स्कूल सह छात्रावास का निर्माण
- ग्रामीण विकास/आपदा प्रबंधन
- जल संसाधन संवर्धन

हरित पहलें

- पिछले 10 वर्षों के दौरान, **423 लाख से अधिक पौधों** के व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से लगभग **18,868 हेक्टेयर** भूमि को हरित कवर में बदलकर पर्यावरणीय संरक्षण पर उल्लेखनीय कार्य हुआ है जो कि **9.46 लाख टन सीओ2 के समतुल्य कार्बन सिंक** के बराबर है।

- कोयला / लिग्नाइट पीएसयू ने मान्यता प्राप्त प्रतिपूरक वनीकरण (एसीए) दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी तक लगभग 3033 हेक्टेयर वनीकृत गैर-वन कोयला रहित भूमि की पहचान की है।

काकरी क्षेत्र, एनसीएल में वृक्षारोपण/जैव -पुनरूद्धार

इको - पार्कों/खान पर्यटन का विकास

- वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 7 पार्कों को स्थानीय पर्यटन सर्किट के साथ एकीकृत करते हुए 261 हेक्टेयर भूमि पर 28 इको पार्कों/खान पर्यटन स्थलों को स्थापित किया गया।

नेयवेली, एनएलसीआईएल में इको-पर्यटन पार्क

कोयला क्षेत्र में खनन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन

आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे-सतही खनिक, फॉग कैनन, मिस्ट स्प्रेयर, व्हील वॉशिंग, मशीनीकृत रोड स्वीपर, सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) को अपनाया जा रहा है और इनकी नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

ईसीएल में कोयला खानें

नेट जीरो लक्ष्य

गैर-नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा की खपत को नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा की समान मात्रा से पूरा किया जाना चाहिए। संधारणीय भविष्य के लिए, हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों जैसे सौर, पवन, और जल विद्युत ऊर्जा की और बढ़ना चाहिए। हमें कार्बन कैप्चर और पुनर्वनीकरण जैसी पहलों के माध्यम से पहले के गैर-नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगों के पर्यावरणीय प्रभाव को भी पूरा करना चाहिए। गैर-नवीकरणीय ऊर्जा खपत को निष्क्रिय करके, हम जलवायु परिर्वतन को कम कर सकते हैं और एक अधिक पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा परिदृश्य का सृजन कर सकते हैं। कोयला पीएसयू द्वारा निर्धारित नेट जीरो लक्ष्य और आज तक उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कोयला / लिग्नाइट पीएसयू	नेट जीरो उपलब्धि लक्ष्य	क्षमता को बढाकर नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की योजना	अभी तक शुरू की गई नवीकरणीय ऊर्जा	
			सौर	पवन
सीआईएल	2025-26	3 GW	41 MW	
एनएलसीआईएल	2030	6 GW	1421 MW	51MW
एससीएल	2024	550 MW	224 MW	
कुल			**1686 MW**	**51 MW**

पहुंचाया कोयला, किया, करोडों घरों को रोशन,
उद्योगों, नौकरियों और सुदूर लोगों का जीवन हुआ गुलशन |

हुई सरल अनेकों खनन प्रक्रिया,
कोरोना के खिलाफ लड़ाई मे, देशवासियों ने कहा शुक्रिया |

बनाया कोयला खनन का नया कीर्तिमान,
आत्मनिर्भर भारत की ओर हुआ देश गतिमान |

आओ, लें संकल्प थामे अमृत महोत्सव की डोर,
ले जाये भारतवर्ष को अमृत काल की ओर |

सत्यमेव जयते

कोयला मंत्रालय

Ministry of Coal

Ministry of Coal